

SHIERRY EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] No. 156] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 2004/आधार 30, 1926

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2004/ASADHA 30, 1926

राज्य सभा सचिवालय

··ं अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2004

सं. आरएस. 7/3/2004-एल.—राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों में राज्य सभा द्वारा 20 जुलाई, 2004 को हुई अपनी बैठक में स्वीकार किए गए निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा आम सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं:—

(नियम 286-303) (नए नियम)

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम में अध्याय XXIII के बाद निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाए:-

अध्याय XXIV

आचार समिति

286. आचार समिति

एक आचार समिति गठित की जाएगी।

287. **गठन**

(1) अध्यक्ष समय-समय पर आचार समिति नामनिर्देशित करेगें जिसमें 10 सदस्य होंगे।

- (2) उप-समिति (1) के अधीन नाम-निर्देशित की गई समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि एक नई समिति नाम-निर्देशित न की जाए।
 - (3) समिति में हुई आकस्मिक रिक्तियां अध्यक्ष द्वारा भरी जाएंगी।

288. सिमिति का अध्यक्ष

- (1) सिमिति का अध्यक्ष सिमिति के सदस्यों में से माननीय सभापति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (2) यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो माननीय सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा।
- (3) यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित रहे तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनेगी।

289. गणपूर्ति

समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पाँच से हो सकेगी।

290. कृत्य

समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, नामतः-

- (क) सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचारण पर ध्यान रखना;
- (ख) सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करना और राज्य सभा को प्रतिवेदन के रूप में आचार संहिता में समय-समय पर संशोधन या परिवर्धन करने के लिए सुळाव देना;
- (ग) सदस्यों के कथित आचरण और अन्य दुराचरण से संबंधित मामलों अथवा सदस्यों द्वारा आचार-संहिता का उल्लंघन किए जाने की जांच करना;
- (घ) स्वप्रेरण से अथवा विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर समय-समय पर आचार विषयक मानदण्डों से संबंधित प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देना।

291. साक्ष्य लेने या पत्र, अभिलेख या दस्तावेज मांगने की शक्ति

(1) यदि समिति अपने कर्तव्य पालन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समळो तो उसे ऐसा मार्ग अपनाने की शक्ति होगी;

परन्तु यह कि यदि यह प्रश्न पैदा हो जाए कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य या प्रलेख की प्रस्तुति समिति के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है, तो यह मुद्दा सभापति के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा;

- (2) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन समिति द्वारा किसी साक्षी, को बुलाया जा सकेगा और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हो।
- (3) यह समिति के स्व विवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने दिए गए किसी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।

292. सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सूचना

प्रत्येक सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार शपथ लेने अथवा प्रतिब्बान करने के 90 दिन के भीतर अपने तथा अपने नजदीकी परिवारजन अर्थात पति/पत्नी, आश्रित पुत्रियों तथा आश्रित पुत्र की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के संबंध में समिति को या समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी प्राधिकृत अधिकारी को सूचना उपलब्ध करानी होगी जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 75क के अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित है।

293. सदस्यों के हितों की पंजिका

- (1) समिति द्वारा अवधारित किए गए रूप में "सदस्यों के हितों की एक पंजिका" रखी जाएगी जिसे सदस्य अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्राप्त कर सकेंगे।
 - (2) पंजिका का रख-रखाव राज्य सभा के प्राधिकार के अंतर्गत किया जायेगा।

(3) समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पंजिका में निहित सूचना आम जनता को दी जा सकती है।

294. हितों की घोषणा

- (1) जब भी किसी सदस्य का सभा या उसकी किसी समिति द्वारा विचार किये जा रहे किसी मामले में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या विशिष्ट धन संबंधी हित हो, तो वह पंजिका में अपने हितों को दर्ज करने के बावजूद ऐसे हित की प्रकृति की घोषणा करेगा और ऐसी घोषणा करने से पूर्व सभा या उसकी समितियों में होने वाले ऐसे किसी वाद-विवाद या मतदान में भाग नहीं लेगा।
- (2) सभा में मत विभाजन होने पर यदि किसी सदस्य के मत को व्यक्तिगत, धन संबंधी या निर्णीत किये जाने वाले विषय के संबंध में प्रत्यक्ष हित के आधार पर चुनौती दी जाती है, तो अध्यक्ष, यदि आवश्यक समळो, चुनौती देने वाले सदस्य से उनकी आपित का सटीक आधार बताने के लिए कह सकते हैं और जिस सदस्य के मत को चुनौती दी गई हो अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं और तब अध्यक्ष यह निर्णय लेंगे कि क्या सदस्य के मत को अनुमति दी जाये या नहीं और उनका निर्णय अंतिम होगा।

बशर्ते कि किसी सदस्य के मत को मत विभाजन होने के तत्काल बाद तथा अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा किये जाने से पूर्व चुनौती दी जाती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्यों के लिए सदस्य का हित प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत या धन संबंधी होना चाहिए तथा पृथक रूप से उस व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए जिसके मत पर प्रश्न उठाया गया हो तथा आम जनता के साथ या तत्संबंधी किसी वर्ग के साथ या किसी विषय पर या सरकार की नीति के साथ सांळा नहीं होना चाहिए।

295. शिकायत करने की प्रक्रिया

- (1) कोई भी व्यक्ति समिति से आरोपित "आचार संबंधी अनेतिक व्यवहार" या किसी सदस्य द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन या किसी सदस्य के हितों की आरोपित गलत सूचना की शिकायत कर सकता है।
 - (2) समिति मामलों को स्वप्रेरणा से भी उठा सकती है।
 - (3) सदस्य भी मामलों को समिति के पास भेज सकते हैं।
- (4) कोई भी शिकायत समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को लिखित रूप में ऐसे रूप एवं स्वरूप में की जायेगी जैसा कि समिति विनिर्दिष्ट करे।
 - (5) शिकायत संयमित भाषा में व्यक्त होगी तथा तथ्यों तक सीमित होगी।
- (6) शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान की घोषणा करनी होगी तथा अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सहायक दस्तावेजी या अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
- (7) समिति शिकायतकर्ता का नाम प्रकट नहीं करेगी, यदि शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है तथा उसे अनुरोध को समुचित कारणों से समिति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।
- (8) केवल मीडिया की अप्रमाणिक रिपोर्ट पर आधारित शिकायत को प्रमाणिक आरोप नहीं माना जाएगा।
 - (9) समिति ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगी जो न्याय-निर्णयाधीन हो तथा इस नियम के उद्देश्य के लिए कि क्या ऐसा मामला न्याय-निर्णयाधीन है या नहीं, समिति के निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

2242 62104-2

296. जांच की प्रक्रिया

- (1) यदि समिति इस बात से संतुष्ट है कि शिकायत उचित रूप में है तथा मामला उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो वह मामले को प्रारंभिक जांच के लिए ले सकती है।
- (2) प्रारंभिक जांच के बाद, यदि समिति द्वारा पाया जाए कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो मामले को छोड़ा जा सकता है।
- (3) यदि यह पाया जाता है कि कोई शिकायत असत्य या खिजाऊ है अथवा दुर्भावना से की गई है तो मामले पर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे के रूप में विचार किया जा सकता है।
- (4) यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो मामले पर समिति द्वारा जांच तथा प्रतिवेदन देने के लिए विचार किया जाएगा।
- (5) समिति अपने अधिदेश को कार्य-रूप देने तथा समिति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए समय-समय पर नियम बना सकती है।
 - (6) समिति सामान्यता अपनी बैठकें बंद कमरे में आयोजित करेगी।

297. दण्ड

जब भी यह पाया जाए कि किसी सदस्य ने कोई अनैतिक आचरण या अन्य कदाचारपूर्ण कार्य किया है या संहिता/नियमों का उल्लंघन किया है, तो समिति निम्नलिखित दण्डों में से एक या उससे अधिक दण्ड देने की सिफारिश कर सकती है:-

- (क) निन्दा;
- (ख) भर्त्सना;
- (ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदन से निलंबन; तथा

(घ) समिति द्वारा उचित समळा गया कोई अन्य दण्ड।

298. प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

आचार समिति का प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

299. प्रतिवेदन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव

प्रतिवेदन के सभा में उपस्थित किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, समिति के अध्यक्ष या समिति के किसी सदस्य के नाम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

300. विचार किए जाने के प्रस्ताव में संशोधन

कोई भी सदस्य प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना, ऐसे रूप में जैसा कि सभापति द्वारा उचित समळा जाए, दे सकता है।

301. प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के बाद प्रस्ताव

प्रतिवेदन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, यह प्रस्ताव कर सकता है कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है या असहमत है या संशोधनों के साथ सहमत है।

302. प्रक्रिया का विनियमन

सभापति, सिमिति या सभा के सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचार के मामलों की जांच से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समळो।

303 नैतिक तथा अन्य कदाचार के प्रश्न को समिति को भेजने के संबंध में सभापति का अधिकार

इन नियमों में किसी बात के होते हुए, सभापति किसी सदस्य के नैतिक तथा अन्य कदाचार से संबंधित प्रश्न को जांच, अन्वेषण तथा प्रतिवेदन देने के लिए आचार समिति को भेज सकता है।

II

नियम 212 थ

उप नियम(1) में 'सात सदस्यों' शब्दों के स्थान पर 'दस सदस्यों' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाये।

!!!

नियम 269

उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1) नियम 268 के अधीन गठित प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य से अधिक नहीं होंगे, जिसमें 10 सदस्य राज्य सभा के सदस्यों में से सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएंगे तथा 21 सदस्य लोक सभा अध्यक्ष द्वारा उस सभा के सदस्यों में से नाम-निर्देशित किए जाएंगे:

IV

तीसरी अनुसूची

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों की वर्तमान तीसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

तीसरी अनुसूची (देखिये नियम 268)

क्रम	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
सं.		
1	2	 3

1	2		3° 3
	भाग-।		
1.	वाणिज्य संबंधी समिति	•	वाणिज्य और उद्योग
2.	गृह कार्य संबंधी समिति	(1)	गृह कार्य
		(2)	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास
3.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	(1)	मानव संसाधन विकास
		(2)	युवक कार्यक्रम और खेल 👢
4.	उद्योग संबंधी समिति	(1)	भारी उद्योग और लोक
			उद्यम
		(2)	लघु उद्योग
		(3)	कृषि और ग्रामीण उद्योग
5.	विळान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन	(1)	विळान और प्रौद्योगिकी
	संबंधी समिति	(2)	अंतरिक्ष
		(3)	महासागर विकास
		(4)	परमाणु ऊर्जा
		(5)	पर्यावरण और वन

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

		(0)	
		(3)	योजना
		(4)	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
15.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति		उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
16.	श्रम संबंधी समिति	(1)	.श्रम और रोजगार
		(2)	वस्त्र 🔭 🕆
17.	पेट्रोलियम और रसायन संबंधी समिति		पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
18.	रेल संबंधी समिति		रेल
19.	शहरी विकास संबंधी समिति	(1)	शहरी विकास
		(2)	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन
20.	जल संसाधन संबंधी समिति		जल संसाधन
	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति ग्रामीण विकास संबंधी समिति	(1)	रसायन और उर्वरक ग्रामीण विकास
		(2)	पंचायती राज
			· *
23.	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	(1)	कोयला और खान
		(2)	इस्पात
24.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	(1)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
		(2)	जनजाति कार्य

योगेन्द्र नारायण्, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2004

No. RS. 7/3/2004-L.—The following amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) as adopted by the Rajya Sabha at its sitting held on the 20th July, 2004, are hereby published for general information:—

I

RULES 286- 303 (NEW RULES)

After chapter XXIII of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, the following chapter be added:-

CHAPTER XXIV

COMMITTEE ON ETHICS

286. Committee on Ethics

There shall be a Committee on Ethics.

287. Constitution

(1) The Chairman shall, from time to time, nominate a Committee on Ethics consisting of ten members.

- (2) The Committee nominated under sub-rule (1) shall hold office until a new Committee is nominated.
 - (3) Casual vacancies in the Committee shall be filled by the Chairman.

288. Chairman of Committee

- (1) The Chairman of the Committee shall be appointed by the Chairman from amongst the members of the Committee.
- (2) If the Chairman of the Committee is for any reason unable to act, the Chairman may similarly appoint another Chairman of the Committee in his place.
- (3) If the Chairman of the Committee is absent from any meeting, the Committee shall choose another member to act as Chairman of the Committee for that meeting.

289. Quorum

The quorum of the Committee shall be five.

290. Functions

The Committee shall have the following functions, namely:-

- (a) to oversee the moral and ethical conduct of members;
- (b) to prepare a Code of Conduct for members and to suggest amendments or additions to the Code from time to time in the form of reports to the Council;
- (c) to examine cases concerning the alleged breach of the Code of Conduct by members as also cases concerning allegations of any other ethical misconduct of members; and
- (d) to tender advice to members from time to time on questions involving ethical standards either *suo motu* or on receiving specific requests.

291 Power to take evidence or call for papers, records or documents

(1) The Committee shall have power to require the attendance of persons or the production of papers or records, if such a course is considered relevant and necessary for the discharge of its duties;

Provided that if any question arises whether the evidence of a person or the production of a document is relevant for the purposes of the Committee, the question shall be referred to the Chairman whose decision shall be final.

- (2) Subject to the provisions of this rule, a witness may be summoned by the Committee and he shall produce such documents as are required for the use of the Committee;
- (3) It shall be in the absolute discretion of the Committee to treat any evidence, oral or documentary, tendered before it as secret or confidential.

292. Information to be furnished by members

Every member shall be required to furnish information within ninety days of his making and subscribing an oath or affirmation under article 99 of the Constitution, relating to his own assets and liabilities as well as the assets and liabilities of his immediate family members namely, spouse, dependent daughters and dependent sons, as provided in the rules framed under Section 75A of the Representation of the People (Third Amendment) Act, 2002.

293. Register of members' interest

- (1) There shall be maintained a 'Register of members' interests' in such form as may be determined by the Committee which shall be available to members for inspection on request.
- (2) The register shall be maintained under the authority of the Council.
- (3) Information contained in the Register may be given to the general public in accordance with such rules and procedures as may be determined by the Committee from time to time.

294. Declaration of interests

- (1) Whenever a member has a personal or specific pecuniary interest (direct or indirect) in a matter being considered by the Council or a Committee thereof, he shall declare the nature of such interest notwithstanding any registration of his interests in the Register, and shall not participate in any debate taking place in the Council or its Committees before making such declaration.
- (2) On a division in the Council if the vote of a member is challenged on the ground of personal, pecuniary or direct interest in the matter to be decided, the chairman may, if he considers necessary, call upon the member making the challenge to state precisely the grounds of his objection, and the member whose vote has been challenged shall state his case, and the Chairman shall then decide whether the vote of the member should be disallowed or not and his decision shall be final.

Provided that the vote of a member is challenged immediately after the division is over and before the result is announced by the Chairman.

Explanation: For the purposes of this rule the interest of the member should be direct, personal or pecuniary and separately belong to the person whose vote is questioned and not in common with the public in general or with any section thereof or on any matter or State policy.

295. Procedure for making complaint

- (1) Any person may make a complaint to the Committee regarding alleged unethical behaviour or breach of the Code of Conduct by a member or alleged incorrect information of a member's interests.
- (2) The Committee may also take up matters suo motu.
- (3) Members may also refer cases to the Committee.
- (4) A complaint should be addressed in writing to the Committee or to an officer authorized by it in such form and manner as the Committee may specify.
- (5) The complaint shall be couched in temperate language and be confined to facts.
- (6) A person making a complaint must declare his identity and submit supporting evidence, documentary or otherwise to substantiate his allegations
- (7) The Committee shall not disclose the name of the complainant, if so requested and if the request is accepted by the Committee for sufficient reasons.
- (8) A complaint based merely on an unsubstantiated media report shall not be entertained.
- (9) The Committee shall not take up any matter which is *sub judice* and the decision of the Committee as to whether such matter is or is not *sub judice* shall for the purposes of this rule be treated as final.

296. Procedure for inquiry

- (1) If the Committee is satisfied that the complaint is in proper form and the matter is within its jurisdiction, it may take up the matter for preliminary inquiry.
- (2) After the preliminary inquiry, if the Committee is of the opinion that there is no *prima facie* case, the matter may be dropped.
- (3) If a complaint is found to be false or vexatious, or made in bad faith, the matter may also be taken up as an issue of breach of parliamentary privilege.
- (4) If the Committee is of the opinion that there is a *prima facie* case, the matter shall be taken up by the Committee for examination and report.
- (5) The Committee may frame rules from time to time to give effect to its mandate and for conducting inquiries either by itself or by any official acting under its authority.

(6) The Committee shall ordinarily hold its meetings in camera.

297. Sanctions

Where it has been found that a member has indulged in unethical behaviour or that there is other misconduct or that the member has contravened the Code/Rules, the Committee may recommend the imposition of one or more of the following sanctions viz.:

- (a) censure;
- (b) reprimand;
- (c) suspension from the House for a specific period; and
- (d) any other sanction determined by the Committee to be appropriate.

298. Presentation of report

The Report of the Committee shall be presented to the Council by the Chairman of the Committee or in his absence by any member of the Committee.

299. Motion for consideration of report

As soon as may be, after a report has been presented, a motion in the name of the Chairman of the Committee or any member of the Committee may be put down that the report be taken into consideration.

300. Amendment to motion for consideration

Any member may give notice of amendment to the motion for consideration of the report in such form as may be considered appropriate by the Chairman.

301. Motion after consideration of report

After the motion for consideration of the report has been carried, the Chairman or any member of the Committee or any other member, as the case may be, may move that the Council agrees, or disagrees or agrees with amendments, with the recommendations contained in the report.

302. Regulation of procedure

The Chairman may issue such directions as he may consider necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the examination of cases with reference to ethical and other misconduct of members either in the Committee or in the Council.

303. Power of Chairman to refer a question of ethical and other misconduct to Committee

Notwithstanding anything contained in these rules, the Chairman may refer any question involving ethical and other misconduct of a member to the Committee for examination, investigation and report.

П

RULE 212 Q

In sub-rule (1), for the words 'seven members', the words 'ten members' be substituted

Ш

RULE 269

For sub-rule (1), the following sub-rule be substituted, namely: -

(1) Each of the Standing Committees constituted under Rule 268 shall consist of not more than 31 members, 10 members nominated by the Chairman from amongst the members of the Council, and 21 members nominated by the Speaker from amongst the members of the House:

IV

and the

THIRD SCHEDULE

For the existing Third Schedule to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, the following Schedule be substituted, namely: -

THIRD SCHEDULE (See Rule 268)

Sl.	Name of Committee	. :::"	Ministries/Departments
No.	4.5		
(1)	(2)		(3)
		Part-	
1.	Committee on Commerce	Section of the sectio	ii Commerce and Industry
2.	Committee on Home Affairs	(1) (2)	Home Affairs Development of North-Eastern Region
	2242 GTlo4-5°		

1	2		3
3,	Committee on Human Resource	(1)	Human Resource
	Development		Development
		(2)	Youth Affairs and Sports
4.	Committee on Industry	(1)	Heavy Industries and Public Enterprises
		(2)	Small Scale Industries
		(3)	Agro and Rural Industries
5.	Committee on Science &	(1)	Science & Technology
	Technology, Environment & forests	(2)	Space
		(3)	Ocean Development
		(4)	Atomic energy
		(5)	Environment & Forests
6.	Committee on Transport, Tourism	(1)	Civil Aviation
	and Culture	(2)	Road Transport and Highways
		(3)	Shipping
		(4)	Tourism
		(5)	Culture
7.	Committee on Health and Family		Health and Family Welfare
8.	Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice	(1) (2)	Law and Justice Personnel, Public Grievances and Pensions
	ī	Part-I	Ī
9.	Committee on Agriculture	(1)	Agriculture
,		(2)	Food Processing Industries
		(2)	1 ood 1 tooossing industries
10.	Committee on Information	(1)	Communications and Information
	Technology		Technology
		(2)	Information & Broadcasting
11.	Committee on Defence		Defence
12.	Committee on Energy	(1)	Non-Conventional Energy Sources
		(2)	Power
13.	Committee on External Affairs	(1)	External Affairs
		(2)	Non Resident Indians Affairs
14.	Committee on Finance	(1)	Finance
		(2)	Company Arrairs
		(3)	Planning
		(4)	Statistics and Programme

1	2	~~ ~	3
15.	Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Consumer Affairs, Food and Public Distribution
16.	Committee on Labour	(1) (2)	Labour and Employment Textiles
17.	Committee on Petroleum & Natural Gas	-	Petroleum & Natural Gas
18.	Committee on Railways		Railways
19.	Committee on Urban Development	(1) (2)	Urban Development Urban Employment and Poverty Alleviation
20.	Committee on Water Resources		Water Resources
21.	Committee on Chemicals and fertilizers		Chemicals and Fertilizers
22.	Committee on Rural Development	(1) (2)	Rural Development Panchayati Raj
23.	Committee on Coal and Steel	(1) (2)	Coal & Mines Steel
24.	Committee on Social Justice & Empowerment	(1) (2)	Social Justice and Empowerment Tribal Affairs

YOGENDRA NARAIN, Secy.-General